अंक 5 : दिसम्बर 2018

1945 से राष्ट्र सेवा में समर्पित

जलांश

केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

संदेश

एस. मसूद हुसैन
अध्यक्ष, के. ज. आ.

विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय जल-विज्ञान परियोजना के अंतर्गत **सतत जल प्रबंधन** पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन *10-11* दिसंबर, *2018* के दौरान भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा केंद्रीय जल आयोग एवं केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड के तकनीकी सहयोग से किया जा रहा है. यह जल प्रबंधन के विभिन्न आयामों पर विचार एवं परिचर्चा का अवसर उपलब्ध कराएगा. केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों की टीम इस मंच पर अपनी विशेषज्ञता एवं अनुभवों को साझा करेगी.

आगे, 13-14 फरवरी 2019 को भुवनेश्वर में होने वाले **अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन** का बुलेटिन जारी कर दिया गया है. सम्मेलन में जल संसाधन क्षेत्र के अग्रणी पेशेवरों द्वारा ज्ञानवर्धक प्रस्तुतियाँ, आधुनिक तकनीक एवं सेवाओं पर आधारित प्रदर्शनी और भारत के सबसे लंबे मृदा बांध, हीराकुंड बांध का अध्ययन दौरा शामिल होगा. हम इस सम्मेलन में सभी संबंधितों की व्यापक भागीदारी की आशा करते हैं.

जल मौसम विज्ञान आंकड़ा प्रसार नीति 2018 मंत्रालय द्वारा नवंबर 2018 में जारी किया गया है जिसमें बांग्लादेश एवं म्यांमार में प्रवाहित होने वाली नदियों से संबन्धित वर्गीकृत आंकड़ा राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी करने के मानदंड को शिथिल किया गया है.

अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर, भारत यूरोपीय संघ जल साझेदारी बेहतर प्रगति कर रही है. जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञों की एक टीम ने **पंचेश्वर बहुद्देशीय परियोजना** के परियोजना स्थल का दौरा किया.

उत्तर कोयल परियोजना की सदस्य (जल योजना व परियोजना), केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में तकनीकी समिति द्वारा निगरानी की जा रही है.

जल क्षेत्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण **कानून** यथा बांध सुरक्षा विधेयक को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में लाए जाने की संभावना है.

हम लगातार विभिन्न तकनीकों और उपकरणों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से स्थान विशेष पर कार्य कर कर रहे अधिकारियों की कौशल सीमा का उन्नयन कर रहे हैं तथा साथ ही जल संसाधनों की देख-रेख कर रहे राज्य सरकार के अधिकारियों की भी क्षमताओं का उन्नयन करने में शामिल हैं .

हम पूरे देश में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अपने महत्वपूर्ण जल गुणवत्ता प्रयोगशाला को उन्नत बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं. इस परिप्रेक्ष्य में कोच्चि, पुणे और गांधीनगर में तीन अतिरिक्त प्रयोगशालाओं को आई एस ओ /आई ई सी *17025:2005* मानक के अनुरूप **एन ए बी एल की आधिकारिक मान्यता** हेतु प्रस्तावित किया गया है. मुझे आशा है कि हमारे क्षेत्रीय संगठनों द्वारा इस मानक के अनुरूप और प्रयोगशालाओं का उन्नयन किया जाएगा.

नव वर्ष 2019 का स्वागत करते हुए , मैं आप सभी को सफल, स्वस्थ दीर्घायु होने और एक नई शुरुआत करने की शुभकामनाएं देता हूं.

घोषणा

जल लोगों की संपदा होने एवं इसका वितरण अनिश्चित होने को देखते हुए, उचित दृष्टिकोण प्रकृति से शिकायत ना करके जल का संरक्षण करना है... जलाशयों में जल के स्थाई संरक्षण हेतु नदियों में विभिन्न स्थानों पर बांध निर्माण करना है।

डॉ. भीमराव अंबेडकर, कटक नवंबर 8, 1945

विषय वस्तु

- केंद्रीय जल आयोग के पदाधिकारियों के दौरे
- उत्तरी कोयल परियोजना
- मैथन जलाशय पर तटबंध
- बाढ़ प्रबंधन पर विशेषज्ञों का संयुक्त समूह
- केंद्रीय जल आयोग पुस्तकालय
- एन ए बी एल मान्यता
- तटीय प्रबंधन सूचना तंत्र
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- ए आई बी पी प्रबोधन
- जल मौसम विज्ञान डाटा प्रसार नीति 2018
- भारत-यूरोपीय संघ जल साझेदारी
- जल क्षेत्रक संघर्ष एवं अभिशासन पीठ
- जलाशय प्रबोधन
- ग्लेशियल झील प्रबोधन
- चक्रवाती तूफान- गाजा
- प्रशिक्षण
- समाचारों में जल क्षेत्र
- दीर्घा (गैलरी)
- इतिहास से

केंद्रीय जल आयोग के पदाधिकारियों का दौरा

माननीय राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा, श्री ए के नायक, मुख्य अभियंता, के. ज. आ., पटना ने के. ज. आ., जीएफ़सीसी, और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के साथ 28.11.2018 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में कटाव स्थल का दौरा किया

गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में कटाव स्थल

श्री मनोज सिन्हा, माननीय संचार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं राज्य मंत्री (रेलवे) ने 28.11.2018 को गाजीपुर जिले के करंदा ब्लॉक में गंगा नदी के बाएँ तट के स्थलों का दौरा किया. इस दौरे के दौरान केंद्रीय जल आयोग एवं जी एफ सी सी के अधिकारियों के साथ सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार की एक टीम माननीय मंत्री के साथ रही. गंगा नदी के बाएँ तट पर कटाव स्थलों में पुरैना, बायेपुर, सोकानी, बदहरिया, रफीपुर, दीनापुर और श्री शिवपूजन बाबा आश्रम शामिल है.

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने सूचित किया कि "गाजीपुर जिले में गंगा नदी के बाएँ तट पर ग्राम समूह- पुरैना, बायेपुर, सोकानी, बदहरिया, रफीपुर, दीनापुर और श्री शिवपूजन बाबा आश्रम की सुरक्षा के लिए जिओ टेक्सटाइल ट्यूब कटर का निर्माण" नामक परियोजना का निर्माण गंगा नदी के बाएँ तट के 3.150 किलोमीटर की सुरक्षा हेतु किया गया है. (अनुमानित लागत -रूपए 12.45 करोड़).

इस दौरे के आधार पर, केंद्रीय जल आयोग/जी एफ सी सी की टीम ने उक्त परियोजना में प्रस्तावित बौल्डर पिचिंग/ लॉन्चिंग ऐप्रन की लंबाई में वृद्धि करने के साथ गाद निक्षेपण की दर में वृद्धि हेतु पार्क्युपाइन के प्रयोग की सलाह दी.

पिथौरागढ़, उत्तराखंड में भूस्खलन स्थल

अक्टूबर 2016 में, पिथौरागढ़ में धारचूला तहसील के खोटीला ग्राम में भूस्खलन हुआ जिससे महाकाली (नेपाल)/काली नदी (भारत) में अवरोध उत्पन्न हुआ. यह नदी भारत एवं नेपाल के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से होकर बहती है. भूस्खलन के परिणामस्वरुप, नदी के प्रवाह में भारी मात्रा में मलबा जमा हो गया और नदी की चौड़ाई कम हो गयी. इसके फलस्वरूप नदी का प्रवाह मुख्य रूप से नेपाल की ओर बाएँ तट पर बहने लगा. जिला प्रशासन के अनुरोध पर, केंद्रीय जल आयोग, एनआईएच, सीएसएमआरएस, जीएसआई, जीएफसीसी के अधिकारियों की एक टीम ने अक्टूबर 2018 में भूस्खलन प्रभावित स्थल का दौरा किया और नवंबर 2018 में अपनी रिपोर्ट सौंपी.

अपनी रिपोर्ट में टीम ने आसन्न चित्र में दर्शाए गए भूस्खलन के भाग 1 एवं भाग 2 में सुझाए गए कुछ त्वरित उपायों को अपनाने का सुझाव दिया. टीम ने नदी प्रवाह, क्रास सेक्शन, एल-सेक्शन इत्यादि की नियमित निगरानी का भी सुझाव दिया.

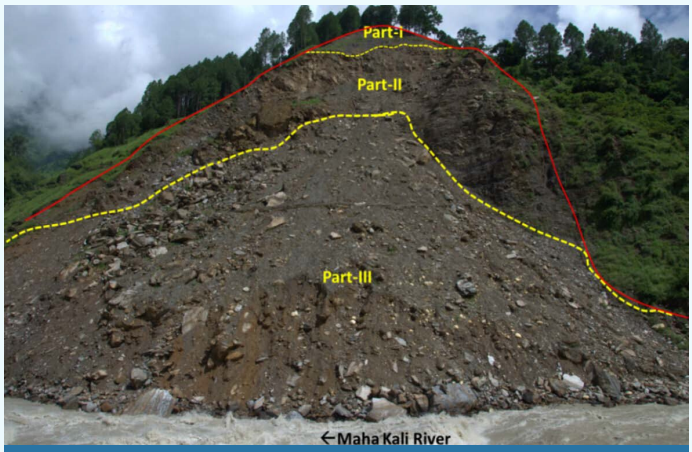

महाकाली (नेपाल)/ काली नदी (भारत) , धारचूला, पिथौरागढ़, उत्तराखंड पर भूस्खलन क्षेत्र

श्री वी डी रॉय, निदेशक, (एमएंडए), के. ज. आ., और श्री जीता राम, उप निदेशक, (एमएंडए) की 20.11.2018 को धोलाईथाबी बैराज परियोजना की प्रबोधन यात्रा

धोलाईथाबी बैराज परियोजना, मणिपुर

508.48 करोड़ की लागत वाली धोलाईथाबी बैराज परियोजना मणिपुर के पूर्वी जिले इम्फ़ाल के गांव में इरिल नदी पर स्थित है. जिसका उद्देश्य बाएँ तट पर स्थित 15 गाँवों एवं दाएं तट के 12 गाँवों में 5500 हेक्टेयर सी सी ए हेतु एक बैराज एवं एक नहर तंत्र का निर्माण करना है. पूर्ण होने पर यह परियोजना, 7545 हेक्टेयर की एक चरम सिंचाई क्षमता का निर्माण करेगी जिससे सिंचन तीव्रता 137.20% होगी. नवंबर 2018 तक कुल सिंचाई क्षमता 5110 हेक्टेयर है. यह परियोजना, पीएमकेएसवाई- एआईबीपी के तहत 99 प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं में शामिल है और मार्च 2019 तक पूर्ण किए जाने हेतु पुनर्निर्धारित है.

हाल ही में, केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों ने परियोजना स्थल का दौरा किया और परियोजना के भौतिक प्रगति के बारे में रिपोर्ट किया- बैराज 100%, गेट 83.33%, कैनाल (i) एल ए 63% (ii) संरचनाओं का सरेखण/अन्वेषण 100%, (iii) आर सी सी सुरंग 83% एवं जल निकास संरचना 100% . यह भी बताया गया कि परियोजना के अंतर्गत सीएडीडब्ल्यूएम का कार्य पूर्ण करने की अवधि मार्च 2020 रखी गयी है .

उत्तर कोयल परियोजना

उत्तरी कोयल जलाशय झारखंड राज्य के गढ़वा एवं पलामू के आदिवासी क्षेत्र में स्थित है. यह परियोजना मूलत: जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 19.3.1980 को आयोजित 13वीं बैठक में स्वीकार की गई थी . इस परियोजना की अनुमानित लागत 113.17 करोड़ थी. इस परियोजना का निर्माण कार्य 1972 में प्रारंभ हुआ एवं 1993 तक जारी रहा. इसी वर्ष, बिहार के वन विभाग द्वारा निर्माण कार्य रोक दिया गया क्योंकि बांध में गेट लगने से बेतला राष्ट्रीय उद्यान एवं पलामू बाघ रिजर्व के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता था. इसके बाद वर्ष 2016 में यह निश्चित किया गया कि पलामू बाघ रिजर्व के मुख्य क्षेत्रों को बचाने हेतु जलाशय की अधिकतम जलाशय स्तर की ऊंचाई को 341.0 मीटर तक ही रखा जाएगा.

तत्पश्चात, अगस्त 2017 में 1622.27 करोड़ की अनुमानित लागत पर उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त हुआ. कैबिनेट के निर्णय अनुसार, जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण द्वारा नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी ई ओ) की अध्यक्षता में, परियोजना संबंधी कार्यों की निगरानी हेतु एक अधिकार प्रदत्त समिति का पुनर्गठन किया गया . उत्तरी कोयल परियोजना के शेष बचे कार्य को पूरा करने हेतु सितंबर 2017 मे केंद्रीय जल आयोग, बिहार एवं झारखंड राज्यों के जल संसाधन विभागों एवं वाप्कोस के बीच एक निविदा अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया.

.

जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण ने भी मई 2017 में उत्तरी कोयल परियोजना के शेष बचे कार्यो को पूरा करने के लिए सदस्य (जल आयोजना एवं परियोजना) केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में एक तकनीकी मूल्यांकन समिति का गठन किया. अभी तक इस समिति की 15 बैठकों का आयोजन किया जा चुका है और अंतिम बैठक 26.11.2018 को संपन्न हुई. इस बैठक के दौरान भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया, द्वितीय स्तर की वन विभाग की मंजूरी की स्थिति, दाहिनी मुख्य नहर का डिजायन एवं अनुमानित लागत, परियोजना के बचे हुए कार्यों से संबन्धित विभिन्न घटकों के विकास की स्थिति, बायीं मुख्य नहर से जुड़े कार्यों के लिए वाप्कोस का भुगतान, मौजूदा संरचना की संरचनात्मक सुरक्षा एवं प्रामाणिकता को पूरा करने संबंधी स्थिति एवं बांध क्षेत्र में बसे गांवों के पुनर्वास की स्थिति से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई.

श्री एस के हलदर, सदस्य, (डबल्यूपीएंडपी) 26.11.2018 को नई दिल्ली में नॉर्थ कोयल परियोजना की 15वीं टीईसी बैठक की अध्यक्षता करते हुए

नदी	**उत्तर कोयल नदी (सोन नदी की सहायिका)**
स्थान	**पलामू जिला, झारखंड**
परियोजना के लाभ	**वार्षिक सिंचाई**- 1,11,521 **हेक्टेयर** **लाभान्वित जिले- पलामू और गढ़वा (झारखंड), औरंगाबाद और गया जिले (बिहार) के सूखा प्रभावित क्षेत्र**
नहर प्रणाली	**मोहम्मदगंज बैराज से उद्गमित**
सकल भंडारण क्षमता	190 **एम सी एम**
लागत	**अनुमानित लागत- रु.** 2391.73 **करोड़** **मार्च** 2016 **तक हुआ खर्च- रु.** 769.09 **करोड़** **शेष कार्य की लागत - रु.** 1622.27 **करोड़**

मैथन जलाशय के चारों ओर रिम तटबंध

झारखंड में, केंद्रीय जल आयोग द्वारा मैथन जलाशय के चारों और रिम तटबंध की व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट (फीजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट) दिनांक 30-11-2018 को दामोदर घाटी निगम को सौंपी दी गई .

मैथन जलाशय के चारों ओर रिम तटबंध का निर्माण, निचली दामोदर क्षेत्र में बाढ़ को कम करने के लिए बिना अतिरिक्त जल मग्नता के और अधिक बाढ़ जल संचयन हेतु प्रस्तावित किया गया है . मैथन जलाशय की संचयन क्षमता को 148 एमसीएम तक बढ़ाने की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने का काम डी वी सी के द्वारा केंद्रीय जल आयोग को सौंपा गया . इस परियोजना की संभावित लागत रुपए 1165 करोड़ व लाभ लागत अनुपात 1.261 है .

श्री पी एम स्कॉट, मुख्य अभियंता, बीएंडबीबीओ, के. ज. आ. और अन्य अधिकारी मैथन जलाशय पर रिम तटबंध के निर्माण की व्यवहार्यता अधध्यन रिपोर्ट के साथ जो की 30.11.2018 को डीवीसी को सौंपी गयी

बाढ़ प्रबंधन पर संयुक्त विशेषज्ञ समूह

भारत एवं भूटान के बीच बाढ़ प्रबंधन पर संयुक्त विशेषज्ञ समूह का गठन बार बार बाढ़ आने के संभावित कारणों एवं प्रभावों तथा भूटान की दक्षिणी तलहटी एवं पास के भारतीय मैदानों की कटाव के बारे में चर्चा एवं आकलन हेतु किया गया. जेजीई की आठवीं बैठक का आयोजन गुवाहाटी में 01.11.2018 से 02.11.2018 के दौरान हुआ . इसके अगले दिन, जेजीई के सदस्यों ने नेरीवालम एवं केन्द्रीय जल आयोग के जल प्रेक्षण स्थल का दौरा किया. भारत की ओर से श्री टीएस मेहरा आयुक्त (बी एंड बी) जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण ने इसका नेतृत्व किया .

जेजीई के अतिरिक्त, दोनों देशों के बीच एक संयुक्त तकनीकी टीम (जेटीटी) का भी गठन हुआ है जिसका नेतृत्व भारत की ओर से मुख्य अभियंता (बी एंड बी बी ओ) केंद्रीय जल आयोग , शिलांग करते हैं .

01.11.2018- 02.11.2018 के दौरान संयुक्त विशेषज्ञ समूह (जेजीई) की 8वीं बैठक में भारत सरकार और भूटान की शाही सरकार के विशेषज्ञ

केंद्रीय जल आयोग पुस्तकालय

ई-ग्रंथालय, एन आई सी, भारत सरकार द्वारा विकसित एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसका उद्देश्य पुस्तकालय की आतंरिक गतिविधियों का स्वचालन करना एवं सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी संगठनों को विभिन्न ऑनलाइन सदस्य सेवाएं प्रदान करना है . इस संदर्भ में, मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संगठनों ने इस सॉफ्टवेयर के उपयोग के लिए शुरुआत कर दी है .

केंद्रीय जल आयोग में जल संसाधन अभियांत्रिकी के विषय पर एवं अन्य संबद्ध तकनीकी विषयों पर विभागीय संदर्भ पुस्तकालय की व्यवस्था है .
ई ग्रंथालय में 88,000 से अधिक रिकॉर्ड की सूची उपलब्ध है . इस सूची को निम्नलिखित यूआरएल के माध्यम से देखा जा सकता है .
https://eg4.nic.in/WaterMinistry/HOME/OPACAdvance.aspx

चूंकि केंद्रीय जल आयोग पुस्तकालय एक तकनीकी विभागीय पुस्तकालय है अतः यह सामान्यतः जनसाधारण के लिए नहीं खोली जाती . हालांकि, अन्य संगठनों के प्रमाणित सदस्यों को पुस्तकालय के प्रयोग की अनुमति है .

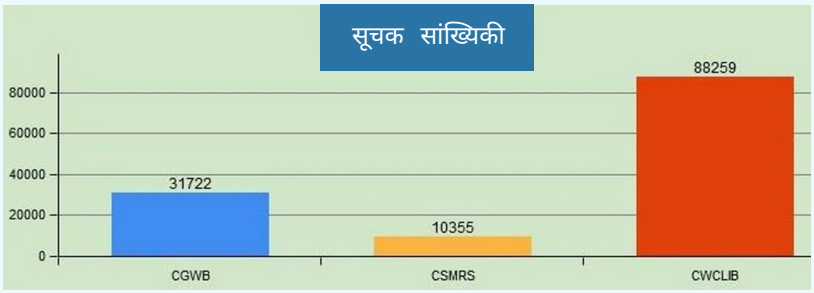

Source https://eg4.nic.in/WaterMinistry/HOME/Default.aspx

एनएबीएल मान्यता

केंद्रीय जल आयोग के 9 जल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं को आईएसओ/आईसी 17025:2005 के अनुसार नवंबर 2018 तक के लिए एनएबीएल मान्यता प्रदान की गयी/सिफ़ारिश की गयी है .

तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों को तटीय डेटा संग्रह में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का प्रदर्शन

केंद्रीय जल आयोग,आईआईटी मद्रास के माध्यम से तटीय पैरामीटर से संबन्धित आंकड़ों के एकत्रीकरण हेतु तटीय प्रबंध सूचना प्रणाली नामक एक परियोजना लागू कर रही है जिसका उपयोग तटीय सुरक्षा संरचना की योजना, रचना एवं प्रबंधन में किया जाएगा . सीएमआईएस परियोजना के अंग के रूप में तीन स्थल 1) देवनारी-तमिलनाडु (2) कराईकाल-पुडुचेरी और (3) पोन्नानी-केरल स्थापित किए गए और पिछले 2 वर्षों से तटीय आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं . एकत्रित किए जा रहे आंकड़ों में ज्वार-भाटा, धारा ,तरंग , तटरेखा परिवर्तन, बेथीमेट्री, तलछट विश्लेषण, चालकता , लवणीय एवं मौसम के मापदंड जैसे वायु , तापमान, वर्षा इत्यादि सम्मिलित है.

केंद्रीय जल आयोग एवं राज्य और संघ शासित प्रदेशों के कर्मचारियों/अधिकारियों को तटीय आंकड़ा एकत्रीकरण के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए सीएमआईएस-हैंडस ऑन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन आईआईटी मद्रास में 19-11-2018 से 29-11-2018 तक किया गया . इस प्रशिक्षण में चयनित तटीय स्थलों पर आंकड़ों के संकलन में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों का भी प्रदर्शन किया गया .

श्री प्रमोद नारायण, निदेशक (डीएसआर), केन्द्रीय जल आयोग

आइएएचआर पत्रिका में प्रकाशित लेख

श्री संजय गिरी एवं श्री प्रमोद नारायण द्वारा लिखित "भारत में बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के तहत गाद प्रेरित समस्याएं" विषय पर एक लेख हाइड्रो लिंक आईएएचआर की एक मुख्य मैगजीन (इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर हाइड्रो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड रिसर्च) में प्रकाशित हुआ .

श्री प्रमोद नारायण, निदेशक (बांध सुरक्षा पुनर्वास) केंद्रीय जल आयोग, परियोजना निदेशक (ड्रिप) हैं. इस जर्नल को निम्नलिखित लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है .

http://iahr.org/Portal/Journals/Hydrolink.aspx

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी प्रबोधन

केंद्रीय जल आयोग, पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत शामिल जल संसाधन परियोजनाओं का व्यापक प्रबोधन कर रहा है . इससे बाधाओं को चिन्हित करने में सहायता मिलती है एवं निधि का समुचित प्रयोग सुनिश्चित होने के साथ-साथ अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकताओं के आकलन का आधार तैयार होता है .

2018-19 के दौरान पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत चल रही 52 प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं की निगरानी केंद्रीय जल आयोग के फील्ड इकाइयों द्वारा किया गया था जिसका उद्देश्य पहली किश्त जारी करने के लिए सुझाव प्रस्ताव भेजना है . इसके अतिरिक्त, 1339.94 करोड़ रुपए जारी करने के सीए के प्रस्ताव को केंद्रीय जल आयोग की सिफ़ारिश के साथ मंत्रालय को भेज दिया गया है .

राज्य का नाम	अनुशंसित राशि (रु. करोड़)
बिहार	6.67
गुजरात	729.05
जम्मू एवं कश्मीर	17.3612
मध्य प्रदेश	86.79
महाराष्ट्र	275.28
मणिपुर	49.73
ओडिशा	138.53
राजस्थान	7.10
तेलंगाना	2.67
उत्तर प्रदेश	26.75
कुल	**1339.94**

उपरोक्त के अतिरिक्त, बोरोलिया परियोजना (असम) का संशोधित लागत अनुमान निचली वर्धा परियोजना (महाराष्ट्र) और राजीव भीमा लिफ्ट सिंचाई योजना (तेलंगाना) को फास्ट ट्रेक प्रोफॉर्मा क्लियरेंस (एफ़टीपीसी) मिल गई है . इस संबंध में जानकारी तालिका में दी गई है .

परियोजना	कुल लागत (रु. करोड़)	एआईबीपी घटक (रु. करोड़)
बोरोलिया , असम	295.97	256.158
निचला वर्धा, महाराष्ट्र	3615.29	2915.61
राजीव भीमा एलआईएस, तेलंगाना	2509.66	1942.66

जल-मौसम विज्ञान डाटा प्रसारण नीति 2018

नवंबर 2018 के दौरान मंत्रालय द्वारा जल मौसम विज्ञान डाटा प्रसारण नीति 2018 जारी की गई है. इस नई नीति के अनुसार क्षेत्र-2 (गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना बेसिन एवं अन्य नदियां व उनकी सहायक नदियां जो बांग्लादेश/म्यांमार में बहती हैं) के लिए डाटा सांझा तंत्र में सुधार किया गया है.

अब यह आंकड़े जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों और राज्य सरकार की सह-बेसिन संस्थाएं जो जल संसाधन से संबंध रखती हैं तथा जल विज्ञान नीति के तहत क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करती हैं, के साथ मुक्त रूप से साझा किए जाएंगे . इस मामले में, डाटा साझेदारी, सुरक्षित लॉगइन/प्रोटोकॉल एवं एक बारगी गोपनीयता घोषणा के माध्यम से की जाएगी.

पुरानी नीति के अन्य प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे और वर्गीकृत डाटा को अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी की अध्यक्षता वाली क्लासिफाइड डाटा रिलीज़ कमेटी (सीडीआरसी) के माध्यम से जारी किया जाएगा.

भारत-यूरोप संघ जल साझेदारी

भारत यूरोप संघ जल समझौता मार्च 2016 में आयोजित हुई तेरहवीं भारत-यूरोप संघ सम्मेलन का परिणाम है . भारत यूरोप संघ जल साझेदारी के तहत, भारत यूरोप संघ जल समझौता तकनीकी सहयोग हेतु निम्नलिखित कार्यकलापों को चिन्हित किया गया है:-

1. सतत नदी बेसिन प्रबंधन
2. पर्यावरणीय प्रवाह
3. नदी संरक्षण
4. भूमिजल प्रयोग एवं पुनर्भरण
5. सिंचाई में जल उपयोग
6. सिंचाई हेतु सौर पंपिंग
7. क्षमता निर्माण
8. जल लेखांकन हेतु मूल योजना
9. शोध,नवोन्मेष,तकनीक

श्री यू पी सिंह, सचिव, जल संसाधन मंत्रालय , नदी विकास और गंगा संरक्षण , ने 26.11.2018 को आईईडबल्यूपी की प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक ली जिसमें भारतीय पक्ष और यूरोपीय संघ के नोडल अधिकारी उपस्थित थे

जल क्षेत्रक संघर्ष एवं अभिशासन पीठ

सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर) और जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में एक जल संसाधन मंत्रालय शोध पीठ - जल संघर्ष एवं अभिशासन की स्थापना के लिए नीति निर्माण हेतु साक्ष्य आधारित एवं स्वतंत्र शोध के साथ, भारत के जल क्षेत्र में विकासशील चुनौतियों का समाधान करने के लिए संस्थाओं को परिवर्तित होने में सक्षम बनाने हेतु समझौता हुआ है. डॉक्टर श्रीनिवास चोकाकुला को जल संसाधन मंत्रालय शोध पीठ - जल संघर्ष एवं अभिशासन नियुक्त किया गया है.

शोध पीठ, शुरुआत में नीति प्रासंगिक शोध परिणामों को लक्षित कर अंतर राज्यीय नदी जल सहयोग एवं विवाद समाधान पर ध्यान देते हुए सीमा के आर-पार व्यापक शोध कार्यसूची पर कार्य करेंगे.शोध पीठ ,समकालीन जल क्षेत्र के मुद्दों और चुनौतियों पर बातचीत के लिए प्रारंभ में एक मंच देते हुए एक चिरस्थाई सी पी आर- -सी डब्लू सी (केन्द्रीय जल आयोग) सहयोगी अनुसंधान संबंधों को बढ़ाने में भी मदद करेंगे .

जलाशय प्रबोधन

केंद्रीय जल आयोग, साप्ताहिक आधार पर, देश भर में 91 जलाशयों की भंडारण स्थिति का प्रबोधन करता है और प्रत्येक गुरुवार को एक बुलेटिन जारी करता है . इन 91 जलाशयों की कुल सक्रिय भंडारण क्षमता 161.993 घन किमी है जो देश में निर्मित अनुमानित 257.812 घन किमी की सक्रिय भंडारण क्षमता का लगभग 63% है.

जलाशय भंडारण बुलेटिन के अनुसार, दिनांक 29.11.2018 को इन जलाशयों में उपलब्ध भंडारण क्षमता 98.353 घन किमी है जो कि इन जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता का 61% है .यह विगत वर्ष में इसी अवधि के दौरान उपलब्ध भंडारण क्षमता का 99% है एवं विगत 10 वर्षों के औसत भंडारण का 95% है .

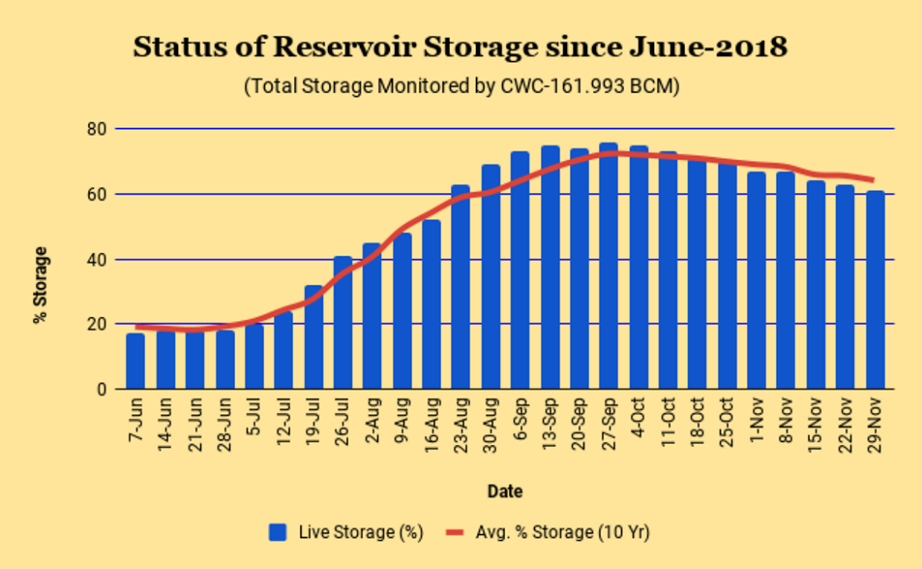

ग्लेशियर झील प्रबोधन

प्रत्येक वर्ष, जून से अक्टूबर के दौरान, केंद्रीय जल आयोग ऐसे ग्लेशियर झील एवं जल निकायों के आकार की निगरानी सेटेलाइट डाटा द्वारा करता है, जो हिमालय क्षेत्र में 50 हेक्टेयर से बड़े है . वर्ष 2009 में इसका डिजिटलीकरण किया गया था और इनके वर्तमान आकार का विश्लेषण वर्ष 2009 के आकार के अनुसार किया जाता है . ग्लेशियर झीलों एवं जल निकायों की संख्या बादल रहित डाटा की उपलब्धता के अनुसार भिन्न होती है . उनकी आकार में बदलाव का सारांश सामने के चार्ट्स में दर्शाया गया है . सितंबर 2018 माह की विस्तृत रिपोर्ट, जिसमें कार्य पद्धति , निष्कर्ष इत्यादि को निम्नलिखित यूआरएल से एक्सेस किया जा सकता है.

http://cwc.gov.in/main/downloads/CWC_lakes_monitor_report_September_2018.pdf

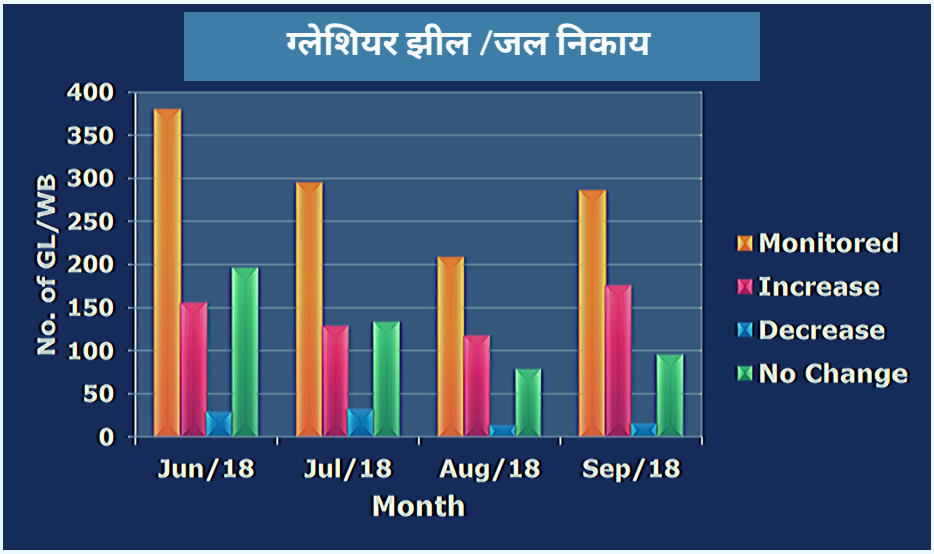

प्रचंड चक्रवाती तूफान- गाजा

10 से 17 नवंबर 2018 के दौरान, प्रचंड चक्रवाती तूफान ने दक्षिण भारत के विभिन्न क्षेत्रों यथा तमिलनाडु, केरल एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र को प्रभावित किया. 10 नवंबर को यह महज एक दबाव क्षेत्र था जो 15 नवंबर को प्रचंड चक्रवात तूफान में परिवर्तित हो गया था . 15 एवं 16 नवंबर की मध्यरात्रि के दौरान चक्रवात ने नागपट्टिनम एवं वेदारण्यम के मध्य तमिलनाडु के तट को पार कर लिया .

चक्रवात ने तमिलनाडु में निचली कावेरी एवं वैगई बेसिन और मध्य केरल में कोट्टायम को व्यापक रूप से प्रभावित किया. गाजा चक्रवात के दौरान, तमिलनाडु के थेणी जिले में सुरुलियार नदी पर बाढ़ निगरानी स्टेशन थेणी पर एवं केरल के कोट्टायम जिले में मीनाचिल नदी पर किडनगूर में 16 नवंबर को तेजी से जल स्तर में वृद्धि हुई .

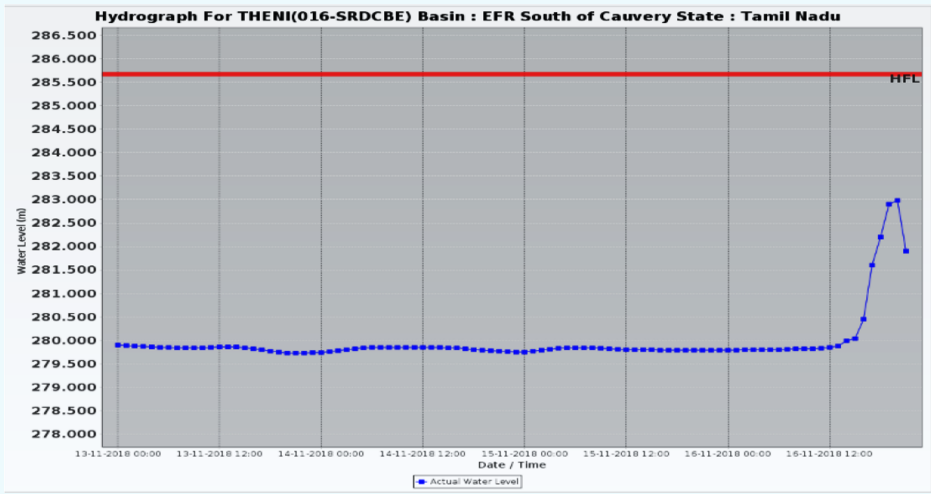

तमिलनाडु में थेणी जिले के थेणी में सुरुलियार नदी के लिए दिनांक 16.11.18 का हाइड्रोग्राफ

प्रशिक्षण

श्री नरेंद्र सिंह शेखावत, उप निदेशक, के. ज. आ., ने 04.11.2018-23.11.2018 के दौरान इस्राइल में "शहरी जल प्रौद्योगिकी और प्रबंधन" पर अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में भाग लिया

12.11.2018 से 16.11.2018 के दौरान गुवाहाटी कैम्पस में "एचओ, एफ़एफ़, डबल्यूक्यू, टेलीमेट्री प्रणाली और ई-स्विस" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

12.11.2018-16.11.2018 के दौरान एमटीबीओ, गांधीनगर में "एचओ, डबल्यूक्यू, टेलीमेट्री और ई-स्विस"पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

श्री वाई के शर्मा, सदस्य (आरएम), के. ज. आ. ने सीएमएसआई पर व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आईआईटी, मद्रास, चेन्नई में 19.11.2018 को उदघाटन किया

श्री एन के माथुर, सदस्य (डीएंडआर), के. ज. आ. 26.11.2018 से 30.11.2018 के दौरान आयोजित "जल विज्ञान परियोजना" प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ के. ज. आ., मुख्यालय, नई दिल्ली में

श्री पी एम स्कॉट, मुख्य इंजीनियर, बीएंडबीबीओ, के. ज. आ., ने 29.11.2019 को शिलांग में "जल वैज्ञानिक और मौसम संबंधी अवलोकन" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया

जल संबंधी समाचार /सूचनाएँ :-

- आंध्र प्रदेश को जलवायु संवेदी जिलों में कृषि परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक से रु.1250 करोड़ का ऋण (लोन) प्राप्त हुआ . (मुंबई मिरर, 5.11.18)
- पोलावरम परियोजना नई उपलब्धियों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है- रेडियल गेट का 17 दिसम्बर को लगाना शुरू किया जाने वाला है . (दि हंस इंडिया, 6.11.18)
- महाराष्ट्र सरकार ने सूखा राहत हेतु केंद्र से रु. 7000 करोड़ की मांग की . (टाइम्स ऑफ इंडिया, 7.11.18)
- पाक 'कूटनीतिक विध्वंस': भारत ने रेटल हायड्रोएलेक्ट्रिक परियोजना के साथ आगे बढ़ने के लिए सरकार जम्मू व कश्मीर में एक टीम को भेजने का निश्चय किया है . (टाइम्स नाऊ, 7.1.18)
- आधारभूत/धरातलीय परियोजनाओं में भूजल के प्रयोग के लिए एन ओ सी को आवश्यक किया गया . (दि न्यू इंडियन एक्सप्रेस, 10.11.18)
- प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी बन्दरगाह का उद्घाटन किया, जो कि बंगाल से भारत के प्रथम अन्तर्देशीय मालवाहक जहाज को उतारेगा. (दि न्यू इंडियन एक्सप्रेस, 12.11.18)
- सिंधु जल: भारत तीन परियोजनाओं में तेज़ी लाने वाला है- इन तीन परियोजनाओं में, प्रथम शाहपुरकांडी बांध परियोजना, द्वितीय पंजाब में सतलुज-ब्यास लिंक एवं तृतीय जम्मू व कश्मीर में उरी परियोजना सम्मिलित हैं . (स्टेट्समैन, 26.11.18)
- एन जी टी कार्यवाही के बाद एनएचपीसी की अरुणाचल परियोजना का कार्य फिर से प्रारम्भ होगा, ग्रीन ट्रिब्यूनल निचली सुबनसीरी एवं दिबांग में हायड्रोएलेक्ट्रिक परियोजना की स्थापना हेतु अपील करेगा . (दि इकोनोमिक टाइम्स, 26.11.18)
- मेकेदातु परियोजना को विरोध के बावजूद केन्द्रीय जल आयोग से अनुमति प्राप्त हुई . यह अनुमति डी पी आर की तैयारी के लिए दी गई . (दि पायनियर , 29.11.18)
- सुप्रीम कोर्ट ने पोलावरम पर लोक सुनवाई का आदेश दिया- केंद्र को उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में सुनवाई के संचालन के विवरण संबंधी हलफ़नामा जारी करने का आदेश दिया . (दि हिन्दू, 30.11.18)
- केरल बाढ़- केंद्र ने राहत कार्य हेतु अतिरिक्त 2500 करोड़ रुपए का अनुमोदन प्रदान किया . इसके पूर्व, केंद्र ने 600 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे . (दि इंडियन एक्सप्रेस, 30.11.18)
- भारत व नेपाल ने पञ्चेश्वर बांध पर अपने तकनीकी मुद्दे सुलझाये। (दि वीक, 30.11.18)

दीर्घा (गैलरी)

श्री एस मसूद हुसैन, अध्यक्ष, के ज आ, श्री राजेंद्र सिंह और श्री तारिक मंसूर, कुलपति, अ मु वि, अलीगढ़, की उपस्थिती में 10.11.18 को एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन संबोधित करते हुए

श्री यू पी सिंह, सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण 17.11.18 को एम एंड ईआरओ, के ज आ, भुवनेश्वर के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए

श्री एन के माथुर, सदस्य (डी एंड आर), के ज आ और अन्य अधिकारी 20.11.18 को वैगई बांध के अधः स्लूइस गेट्स का निरीक्षण करते हुए

इतिहास के पन्नों से- केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष

नाम	से	तक
ए एन खोसला	05-04-1945	16-06-1953
कंवर सैन	17-06-1953	15-10-1958
एम हयात	16-10-1958	31-03-1961
एस एस कुमार	01-04-1961	14-07-1962
एम आर चोपड़ा	15-07-1962	17-08-1966
सी एल हांडा	18-08-1966	07-12-1966
डी बी आनंद	08-12-1966	05-06-1968
जी ए नरसिंह राव	06-06-1968	12-02-1970
एस के जैन	29-03-1970	16-01-1974
डॉ वाई के मूर्ति	25-05-1974	31-10-1978
डॉ के सी थॉमस	01-11-1978	30-06-1980
आर घोष	01-07-1980	30-09-1981
सी सी पटेल	01-10-1981	03-01-1982
आर घोष	04-01-1982	03-07-1982
एम जी पाध्ये	05-07-1982	15-09-1982
प्रीतम सिंह	05-10-1982	31-12-1984
गोकुल प्रसाद	01-01-1985	30-04-1985
एन के शर्मा	01-05-1985	24-09-1985
एम ए चितले	25-09-1985	22-02-1989
एम एस राव	23-02-1989	30-06-1989
आर बी शाह	01-07-1989	28-02-1990
वी बी पटेल	29-03-1990	31-07-1991
डॉ सी डी थट्टे	16-01-1992	10-09-1992
एम एस रेड्डी	11-09-1992	06-03-1994

नाम	से	तक
ए बी जोशी	07-03-1994	31-07-1995
रमेश चन्द्रा	01-08-1995	31-12-1997
ज़ेड हसन	01-01-1998	24-09-1998
ए डी मोहिले	25-09-1998	31-08-2000
ज़ेड हसन	01-09-2000	22-11-2000
आर एस प्रसाद	23-11-2000	28-02-2001
डॉ बी के मित्तल	01-03-2001	31-07-2001
सुरेश चन्द्रा	01-08-2001	31-10-2001
श्रीमती राधा सिंह	01-11-2001	02-01-2002
सुरेश चन्द्रा	03-01-2002	31-10-2002
आर जेयसीलन	01-11-2002	30-11-2006
एस के दास	01-12-2006	31-07-2007
बी एस अहूजा	01-08-2007	31-03-2008
एस मनोहरन	01-04-2008	15-04-2008
ए के बजाज	16-04-2008	31-08-2011
आर सी झा	01-09-2011	31-07-2012
एस पी काकरन	01-08-2012	31-10-2012
राजेश कुमार	01-11-2012	31-07-2013
बिभास कुमार	01-08-2013	31-10-2013
ए बी पाण्ड्या	05-11-2013	31-12-2015
जी एस झा	01-01-2016	31-01-2017
नरेंद्र कुमार	02-03-2017	31-10-2017
एस मसूद हुसैन	18-12-2017	

प्रकाशक :
जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग
द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन
रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066
दूरभाष : 011 2958 3270/71
ई मेल : media-cwc@gov.in

केन्द्रीय जल आयोग
जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय,
भारत सरकार का एक सम्बद्ध कार्यालय

CWC.GOV.IN
CWCOfficial.GoI
CWCOfficial_GoI
CWCOfficialGoI